विशेषज्ञों ने की भारतीय मध्यस्था के भविष्य पर चर्चा

■ देहरादून (एसएनबी)।

यूपीईएस के स्कूल ऑफ लॉ द्वारा प्रतिष्ठित कानूनी सम्मेलन श्रृंखला एडाप्ट या पेरिश के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम में इस वर्ष की थीम 'भारतीय मध्यस्थता एक दोराहे पर: सुधार, विरोध और एक मयस्थता केंद्र के रूप में भविष्य' पर न्यायविदों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की।

कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) विक्रमजीत सेन और न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) हेमंत गुप्ता (अध्यक्ष इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर) ने थीम पर चर्चा की। वहीं, राउंडटेबल चर्चाओं और पैनल सत्रों में भारत की मध्यस्थता प्रणाली के सामने संरचनात्मक और सांस्कृतिक चुनौतियों को लेकर संवाद हुआ। कार्यक्रम में भारत का बदलता मध्यस्थता रुख, प्रक्रिया में विलंब, मध्यस्थों की जवाबदेही, नैतिकता व स्वायत्तता, न्यायिक हस्तक्षेप, प्रवर्तन की चुनौतियां, और भारत का मध्यस्थता हब बनने का भविष्य जैसे विषयों पर चर्चा की गई। यूपीईएस स्कूल आफ लॉ के डीन डा. अभिषेक सिन्हा ने कहा कि भारत इस समय मध्यस्थता की दिशा में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एडाप्ट या पेरिश जैसे आयोजनों के जरिये विचारशील और क्रियाशील लोगों को एक मंच पर लाकर सिस्टम की खामियों पर चर्चा और सुधार की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीडब्ल्यू लीगल वर्ल्ड द्वारा नार्थ जोन में तीसरा और एनआईआरएफ 2024 रैंकिंग में भारत में 28वां स्थान प्राप्त करने वाला यूपीईएस स्कूल आफ लॉ देश का एक अग्रणी विधि शिक्षा संस्थान बन चुका है।

चर्चा में भाग लेने वाले विशेषज्ञ।